(d) whether it is also a fact that foreign companies have offered to take over some of the sick textile units ; and

(e) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY) : (a) and (b) Govt. would welcome any viable proposal for cooperativisation of NTC and other private sector textile mills. A number of discussions have been held with Labour Unions and many of the doubts have been clarified. However, no concrete proposals have been received.

(c) Govt. have approved a turn around strategy for NTC mills. The key elements of the strategy for rationalisation of surplus workforce through implementation of Voluntary Retirement Scheme, modernisation of mills under NTC, financial and managerial re-structuring etc. For the rationalisation of surplus workers/staff, the financial requirement has been estimated at Rs. 689 crores covering 79,982 workers|staff. For modernisation the requirements are Rs. 532 crores. However, in case of private sector textile mills, financial and other requirements will be worked out on receiving concrete proposal.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

Hike in pices of Staple Fibre

2708. SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA : Will the Minister of TEXTILES be pleased to state :

(a) whether the producers of fibers have resorted to price hike in viscose staple fibre (VSF) and polyester staple fibre (PSF);

(b) if so, the details thereof alongwith the extent of price hike resorted to during the last five years;

(c) the reaction of Indian spinners association (ISA) thereto; and

(d) what are the details of measures taken|proposed to be taken to regulate prices of viscose staple fibre and polyester staple fibre to protect the interest of consumers ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY) : (a) and (b) The current weighted average price of Viscose Staple Fibre and Polyester Staple Fibre is Rs. 61.56 per Kg. and Rs. 76.54 pre Kg. respectively as against Rs. 33.43 and 83.28 per Kg. prevailing in March, 1989.

(c) The user industry of Viscose and Polyester Staple Fibres including Indian Spinners Associated have been emphasing the need for downward revision of both Viscose and Polyester Staple Fibre prices.

(d) The prices of man-made fibres|yarns including Viscose Staple Fibre and Polyester Staple Fibre are primarily governed by the demand, supply market forces. However, in order to regulate the prices of these fibres/yarns, Govt. have from time to time taken various policy initiatives such as liberalisation of industrial policy to encourage creation of fresh capacity rationalisation of fiscal levies, etc. of man-made fibres|yarns.

अन्य क्षेत्रों की तुलना में विद्युत चालित करघा क्षेत्र में कपड़े का उत्पादन

2709. **श्री राम जेठमलानी :**

श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अन्य क्षेत्रों की तुलना में विद्युत चालित करघा क्षेत्र में कपड़े का वार्षिक उत्पादन सबसे अधिक होता है;

(ख) यदि हां, तो कपड़े के कुल उत्पादन में से इस क्षेत्र में कपड़े के उत्पादन का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उद्यमियों को वित्तीय सहायता के रूप में कोई धनराशि निर्धारित की है;

(घ) यदि हां तो कितनी धनराशि निर्धारित की गई है तथा उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं के नाम क्या हैं, और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक विद्युत चालित करघा क्षेत्र में कपड़े के वार्षिक उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी): (क) जी हां।

(ख) विद्युतकरघा क्षेत्र में तैयार किये गये कपड़े की प्रतिशतता देश में तैयार किये गए कुल कपड़े का 72 प्रतिशत आंकी गई है।

(ग) तथा (घ) सरकार ने उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में कोई राशि उद्दिष्ट नहीं की है। तथापि, सरकार ने विद्युतकरघा क्षेत्र की सहायता के लिए विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों तथा कम्प्यूटर सहायित डिजाइन केन्द्रों की स्थापना के लिए निधियां उत्कृष्ट की है। विद्युतकरघा उद्यमियों को की गई सहायता के लिए एस आई डी बी आई तथा नाबार्ड द्वारा बैंकों का पुनर्वित्त पोषण किया जाता है।

(ङ) आठवीं योजना के अन्तिम वर्ष तक विद्युतकरघा क्षेत्र में लगभग 30000 मि. मीटर कपड़ा उत्पादित किये जाने की आशा है।

कपास का उत्पादन और उपलब्धता

2710. **डा. जिनेन्द्र कुमार जैन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू कपास वर्ष के दौरान कपास की 172 लाख गांठों का उत्पादन होने की संभावना है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का वास्तविक अनुमान क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश में कपास की कीमतों की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास की कम कीमतों के कारण भारतीय उद्यमियों द्वारा कपास का आयात करने का निर्णय लिया जा रहा है;

(घ) क्या यह भी सच है कि यद्यपि पिछले वर्ष कपास की 17.85 लाख गांठों के निर्यात का लक्ष्य था किन्तु केवल 13.8 लाख गांठें ही निर्यात की जा सकीं!

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या है; और

(च) देश में कपास की खपत की तुलना में उसकी बढ़ी हुई उपलब्धता तथा इसके निर्यात की कम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कपड़े के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या तात्कालिक और दीर्घगामी कदम उठाये जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) कपास सलाहकार बोर्ड ने 8-11-93 को हुई अपनी बैठक में वर्ष 1993-94 के कपास मौसम के दौरान कपास की कुल 135 लाख गांठ का उत्पादन होने का अनुमान लगाया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) तथा (ङ) पिछले वर्ष निर्यात के लिए कपास की 17.85 लाख गांठों को रिलीज किया गया था जिसमें से 31-8-93 तक 13.768 लाख गांठों का जहाज पर लदान कर दिया गया था।

(च) सरकार ने यार्न तथा क्लाथ उत्पादन में वृद्धि सहित वस्त्रों के उत्पादन में वृद्धि के लिए कई कदम उठाए हैं जैसे कि—

(1) क्षेत्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अध्याधीन क्षमताओं के सृजन तथा विस्तार पर प्रतिबंध हटाना।

(2) सौ प्रतिशत निर्यात उन्मुख एककों, एक लाख से अधिक की क्षमता वाले शहरों की परिधि से 25 किलो मीटर के भीतर पड़ने वाले एकक और यदि वह 24-7-91 की स्थिति के अनुसार सरकारी तौर पर घोषित किए औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित नहीं है के मामलों को छोड़कर शेष में लाइसेंस की अपेक्षाओं को समाप्त करना।